who deserted in the wake of Operation Blue Star would be rehabilitated in Public Sector Undertakings, (4)[1] the cases of persons detained would be reviewed, (5) a judicial enquiry would be held into the death of Shri Jagdev Singh Khudian, Akali Dal, M.P., (6) prisoners who are languishing in jail for minor offences would be released, (7) a separate Ministry for small industries would be created, (8) instructions would be given for announcement of enhanced prices for agricultural produce taking into account the increase in general prices.

(b) The information is being collected and will he laid on the Table of the House.

पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में मारे गए व्यक्ति

222. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई सरकार के बनने के बाद पंजाब तथा कश्मीर में आज तक कुल कितने व्यक्ति मारे गए हैं और मारे गए उपरोक्त व्यक्तियों में से पुलिस कर्मियों तथा सिविलियनों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार कश्मीर और पंजाब समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई कदम उठा रही है या कोई नीति या योजना बना रही है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गृह मंत्री की पुत्री के अपहरण-कर्ताओं को उनकी रिहाई के बाद पुनः गिरफ्तार करने का लिए प्रयास न करने तथा वे कहां पर हैं इस पर निगाह न रखे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कश्मीर में फ़ारूख अब्दुल्ला सरकार द्वारा इस्तीफ़ा देने के बाद अब तक कितनी जान व माल की हानि हुई है और राज्य में कुल कितने घंटों तक कर्फ्यू लगा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 दिसम्बर, 1989 से 10 मार्च, 1990 के दौरान पंजाब में 345 नागरिक और 77 पुलिस कर्मी मारे गए । जम्मू और कश्मीर में 6 दिसम्बर, 1989 से 5 मार्च, 1990 के दौरान 83 व्यक्ति मारे गए परन्तु मारे गए नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) दोनों राज्यों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है । संबंधित राज्य सरकारों ने स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तथा अन्य उपाय किए हैं । आवश्यकता पड़ने पर अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि को तैनात करके केन्द्रीय सहायता भी दी गई है । गत वर्षों के दौरान दोनों राज्यों में समस्या और भी जटिल हो गई है तथा सभी पार्टियों के सहयोग से समाधान ढूंढने की आवश्यकता है । इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से चर्चा की गई है ।

(ग) उचित कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार निगरानी रख रही है ।

(घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से इस बारे में ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

223. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की राज्य-वार संख्या क्या है और उन्हें कब तक टेलीफ़ोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जायेंगे और इस संबंध में राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, कोटा, और जोधपुर में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की श्रेणीवार संख्या क्या है और उन सबको कब तक टेलीफ़ोन है कनेक्शन उपलब्ध करा दिए

जायेंगे और शीघ्र टेलीफ़ोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपरोक्त सभी आठ शहरों में टेलीफ़ोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक उपलब्ध कराए गए टेलीफ़ोन कनेक्शनों की वास्तविक संख्या क्या है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राजस्थान के गांवों में टेलीफ़ोन कनेक्शन, एस० टी० डी० सुविधा, नई तकनीक से संबंधित कार्य, नई लाइन बिछाने और टेलीफ़ोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों को वास्तव में किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकरण

224. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं, तथा जहां ऐसी सलाहकार समितियां कार्य नहीं कर रही हैं ;

(ख) जो समितियां वर्तमान में कार्य नहीं कर रही हैं उनका कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हो गया था और उन्हें अब तक पुनर्गठित न किए जाने के क्या कारण हैं, उन्हें कब तक पुनर्गठित कर दिए जाने की संभावना है और इस संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है ;

(ग) देश के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं तथा जहां ऐसी समितियां कार्य नहीं कर रही हैं, उनका कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हो गया था और अब तक पुनर्गठित न किए जाने के क्या कारण हैं, उन्हें कब तक पुनर्गठित किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) राजस्थान के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनके लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जाती है और उनके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और उन शहरों में इन समितियों के कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

I. इस समय कार्य कर रही दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के नाम:

राज्य

1. बिहार

संघ राज्य क्षेत्र

1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2. दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दिव

शहर

1. अमृतसर
2. लुधियाना

II. उन दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समितियों के नाम जिनकी समयावधि निम्नलिखित तारीखों को समाप्त हो गई हैं :—